Publication	**Hari Bhoomi**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	The Edit Desk
Date	28/06/2025	**Page no**	8
CCM	125.13		

Amritkal of cooperatives in India

भारत में सहकारिता का अमृतकाल

विश्लेषण
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

सहकारिता समितियों को उनकी क्षमता का अहसास कराने में मदद करने के लिए ढांचागत निर्माण सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जब से शुरू किया है, सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। अमित शाह का यह स्वप्न लम्बे समय से था कि हम भारत में सहकारिता क्षेत्र का भरपूर विकास करके उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करें जो अभी भी किन्हीं कारणों से विकास की धारा से वंचित रहे हैं। सहकारिता के सिद्धांत दरअसल सबकी उन्नति व सबके विकास में विश्वास करता है। सहकारिता मंत्रालय अपने सात सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत की जन-स्थिति में सुधार की पहल कर रहा है।

भारत का यह अमृतकाल है। इस काल की अर्जित उपलब्धियां आने वाले समय में भारतीय जनता को गर्व से भर देंगी। अमृत काल जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्धि की यात्रा है। भारत में सहकारिता आंदोलन आजादी से भी पहले जारी था। ऐसा मानते हैं कि यह सहकारिता आन्दोलन सवा सौ साल पुराना है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इसका विशेष मंत्रालय बना, जिसका मुख्य जनादेश 'सहयोग से समृद्धि' की दृष्टि को साकार करना है।

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को विस्तारित करना है। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है और साथ-साथ उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत निर्माण करना है। सहकारिता समितियों को उनकी क्षमता का अहसास कराने में मदद करने के लिए ढांचागत निर्माण सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जब से शुरू किया है, सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री अमित शाह का यह स्वप्न बहुत लम्बे समय से था कि हम भारत में एक बार सहकारिता क्षेत्र का भरपूर विकास करके उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करें जो अभी भी किन्हीं कारणों से विकास की धारा से वंचित रहे हैं। सहकारिता के सिद्धांत दरअसल सबकी उन्नति व सबके विकास में विश्वास करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सहकारिता मंत्रालय अपने सात सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत की जन-स्थिति में सुधार की पहल कर रहा है। यथा खुली और स्वैच्छिक सदस्यता का इसमें भरपूर प्रावधान है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण के साथ सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को स्थापित करके चल रहा है। व्यापक शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना पर बल देने की प्रतिबद्धता है। सहकारिता समितियों के बीच सहयोग और समुदाय के लिए चिंता भी इसके सैद्धांतिक पहलू हैं।

अब जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के पंच प्रण को जनमानस में रखा है, तब से सहकारिता के स्वरूप में और सघन विकसित भारतोन्नति को सहयोग मिल रहा है। 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए अमृत काल आह्वान के पंच प्रण कुछ इस प्रकार थे- विकसित भारत का लक्ष्य, औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटा दें। अपनी जड़ों पर गर्व करें। एकता यानी राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और नागरिकों में कर्तव्य की भावना। यह वे प्रण हैं जिससे सच में भारत की छवि बदली जा सकती है। सहकारिता के लिए यह सब सूत्र हैं क्योंकि पंच प्रण से सबके साथ विकास व समृद्धि की नई परिभाषा रची जा सकती है और सबके आत्म गौरव को सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। विश्व स्तर पर सहकारिता के विविध प्रयत्न पर भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह की नजर रहती है। वह चाहते हैं कि भारतीय नागरिक चाहे वह गरीब हो, दलित हों, दमित हों, महिलाएं हों या दिव्यांगजन हों, सबको सहकारिता का लाभ मिले। सहकारिता की भावना से सभी आगे बढ़ें। सहकारिता से सभी एक दूसरे के लिए कार्य करें क्योंकि अमित शाह की दृष्टि में परमार्थ का कार्य ही तो सहकारिता का कार्य है। एक-दूसरे का

सहयोग ही तो परमार्थ का कार्य है। सहकारिता का कार्य है। यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम का अभिभाषण स्मरण आ रहा है। इस अभिभाषण में अमित शाह ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान सहकारिता के विस्तार, इस क्षेत्र में शुचिता लाने, सहकारी संस्थाओं को समृद्ध बनाने, कई नए क्षेत्रों में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और भारत के हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे। यह एक बड़ी संकल्पना है कि भारत की 140 करोड़ वाली आबादी सहकारिता से जुड़े। सहकारिता को समझे। सहकारिता आन्दोलन में सम्मिलित हो। अमृतकाल में सहकारिता का अमृत-समय का हस्ताक्षर पूरे विश्व में भारत की ओर से अंकित करे। वस्तुतः आत्मनिर्भरता की दिशा में यह कार्य है। अमित शाह यह जानते हैं कि अमृत काल की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कुछ है तो वह सहकारिता। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। समृद्ध नहीं बन सकेगा। नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के नारे को यदि जमीनी स्तर पर देखना है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर आमजन को सहकारिता से जोड़ने की आवश्यकता है। यदि अमृत काल में भारत के 2047 के संकल्प को भी चरितार्थ करना है तो सहकारिता से किया जा सकता है। इसे एक विकसित भारत का मॉडल तैयार करने की कोशिश के रूप में हम समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन-आईसीए की स्थापना 1895 में हुई थी। यह सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है। यह विश्व की सहकारी संस्थाओं को एकीकृत करता है और उनका प्रतिनिधित्व व देखरेख करता है। आईसीए सहकारी समितियों के लिए और उनके बारे में ज्ञान, विशेषज्ञता और समन्वित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आवाज और मंच प्रदान करने वाला संगठन है। सभी को यह ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। आधुनिक सहकारी आंदोलन की जन्मस्थली 'रॉचडेल म्यूजियम' में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन-आईसीए की सहकारी सांस्कृतिक विरासत कार्य समूह की बैठक होने वाली है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 विशेष सेलीब्रेशन के ही तहत यह समूह 25 ऐतिहासिक सहकारी स्थलों का डिजिटल वर्ल्ड मैप लॉन्च करने की योजना बना चुका है। यह संगठन सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों की पहचान के लिए वैश्विक दिशा-निर्देश तैयार करने वाला है। खास बात यह है कि इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी आंदोलन के महान अग्रदूतों, परिवर्तनकारियों व समर्पित लोगों की विरासत को उजागर करना और उस परंपरा को सम्मान देना है जिसने इस वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया। अमित शाह की योजना है कि देश के सहकारिता आंदोलन को इस महान प्रदर्शनी में सम्मिलित किया जाए और भारतीय सहकारिता की दुंदुभी पूरे विश्व में बजे। देखा जाए तो सहकारिता की भारतीय यात्रा को उनकी सोच से अब प्रतिबिंबित करना जरूरी है क्योंकि अमित शाह के इरादे बहुत नेक हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और विभिन्न आयोजनों में इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता आंदोलन की चर्चा इसकी विफलताओं तक सीमित नहीं रह सकती। इफको, कृभको, अमूल और नैफेड जैसी संस्थाओं ने सफलता की कई कहानियां गढ़ी हैं। देशभर के किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाएं ही इस आंदोलन की असली रीढ़ हैं। सहकार से समृद्धि की इस बहुदेशीय उल्लेखनीय उपलब्धि का देश को बहुत लाभ मिलने वाला है।

(लेखक केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में वेयर प्रोफेसर हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

****

Downloaded from
SAMVAD